



## सम्पादक की कलम से

### फटकार की जरूरत थी

भ्रामक विज्ञापनों की सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंतजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई। अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर अदालत की अवमानना करने पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने आदेश जारी किया कि वह बड़े साइज में माफीनामा का विज्ञापन जारी करें। रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि माफीनामा 67 अखबारों में दिया गया है। इस पर अदालत ने जानना चाहा कि क्या यह पिछले विज्ञापनों के आकार का था। रोहतगी के इस पर केवल दस लाख रुपये खर्च करने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही, यह भी कहा कि हमें पंतजलि के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने के लिए आईएमए पर एक हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की गई है जिस पर अदालत ने प्रॉक्सि याचिका होने का संदेह व्यक्त किया। केंद्र को इस पर जागना चाहिए कहे हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी लनाइ लगाई। पंतजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। यह सुनवाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर जारी है। पंतजलि योगपीठ को भी अब सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा, जुर्माना और ब्याज के रूप में उसे साढ़े चार करोड़ रुपये भी अदा करने हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार रामदेव की नेटवर्क चौदह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की है। पंतजलि का कुल रेवन्यू तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। निःसंदेह उन्होंने आयुर्वेद और योग को पुनः प्रचारित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा, योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति आमजन में लालक पैदा करने में भी उन्होंने महती भूमिका निभाई है। मगर इसके लिए भ्रम फैलाने या भ्रामक विज्ञापनों के जरिए जनता को बर्गलाने की उन्हें छूट तो नहीं ही मिल सकती। मंत्रालय को भी इसके लिए दोषी माना जाना जरूरी है। बात यहां अकेले पंतजलि की नहीं है, बल्कि कोई भी कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए यदि इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करती है तो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, भविष्य में भी इस तरह की हकत करने पर भारी जुर्माना जड़ा जाना चाहिए। मरीजों और उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जिस तरह की लापरवाही अपने यहां जारी है, उसे रोकने के कड़े कदम तत्काल उठाए जाने बेहद जरूरी हैं।



PATANJALI

## कुछ विशेष

### वादे नहीं नतीजा चाहिए

कई वजहों हमारा पर्यावरण और वातावरण दूषित हो रहा है, जिसके हम किस्तों में शिकार बन रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण हम पहले से ही कई बीमारियों की जद में हैं, लगातार प्रदूषण के कारण हमारी सांसें उखड़ रही हैं तो आए दिन जलवायु परिवर्तन की वजहों से हमें अकल्पनीय विपत्तियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उस पर घातक व मारक माइक्रो प्लास्टिक ने हमें चिंता में डाल दिया है। प्लास्टिक के कण जाने-अनजाने में हमारी आंखों से होते हुए शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच रहे हैं, जो हमारे दिमाग पर भी असर डालने लगा है। दिमाग तक असर डालने का मतलब मानव जाति के लिए प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण खतरनाक संदेश दे रहे हैं। इसलिए हमें इस खतरे को देखते हुए पहले ही चेत जाना चाहिए।



युनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको एंड हेल्थ साइंसेज से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में यह दावा किया है कि माइक्रो प्लास्टिक ने हमें गहरे तौर पर अपने शिकंजे में ले लिया है, इससे घुटका पाने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे, वरना स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। अध्ययन के मुताबिक प्लास्टिक प्रदूषण के महीन कण भोजन, पानी और हवा में घुल चुके हैं जो न केवल हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि हमारे अंतों से होते हुए शरीर के अन्य अहम अंगों जैसे गुर्दा, लीवर और मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। दूसरा अध्ययन यह भी बताता है कि माइक्रो प्लास्टिक समुद्री जानवर और पौधों में भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, हम जिस बोतल बंद पानी को शान से शुद्धता की दुहाई देकर पीते हैं उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक के अंश मिल रहे हैं। यह बेहद महीन कण होते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो अत्यंत जहरीले और केमिकल की शक्ल में होते हैं। आज प्लास्टिक किसी न किसी रूप में घर-घर में घुस चुका है जिससे घुटका पाना बेहद कठिन प्रतीत होता है। प्लास्टिक कप, थर्मोकोल, सजावट के समान, प्लास्टिक स्ट्रॉ, पैकेजिंग फिल्म, पीवीसी बैनर, गुब्बारे लगाने वाली प्लास्टिक की डांडिया, प्लास्टिक बैग, झंडा, टॉफी कैंडी के स्टिक, प्लास्टिक के घबन, शादी कार्ड, मिठाई के डब्बे, दवा की की बोतलें, बाल्टी आदि से लेकर सैंकड़ों परलू वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन व्यवहार में हैं, उनसे घुटका पाना बेहद कठिन प्रतीत होता

है। हालांकि सरकार और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की पहल से सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प समय-समय पर सुझाए गए हैं। कई योजनाओं पर काम भी चल रहे हैं। मगर इसके खतरनाक परिणाम को लोग अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मोटा-मोटी जूट बैग, प्लांटिन, सिलिकॉन, स्टेनलेस स्टील, कांच, मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के उत्पादों का इस्तेमाल करके हम इस खतरे से थोड़ा बच सकते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण वन्य जीवन और आमजन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और इससे निकलने वाले जहरीले रसायन भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे घातक जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा की पहचान करने के लिए चूहों पर अध्ययन किया जिसमें पाया कि चूहे तो सिर्फ चार सप्ताह के लिए माइक्रो प्लास्टिक के संपर्क में आए थे तब उनमें कई तरह की खतरनाक बदलाव देखे गए। शोधकर्ताओं ने इंसानी शरीर में जमा होते माइक्रो प्लास्टिक को लेकर गहरी चिंता जताई है क्योंकि धीरे-धीरे हमारे शरीर के अंगों से होते हुए अब यह इंसानी मस्तिष्क को प्रभावित करने लगा है। सरकार इस समस्या के निदान के लिए कार्य तो कर रही है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई जो चिंताजनक है। गौरतलब है कि पूरे देश में एक जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक के 20 आइटमों को प्रतिबंधित किया गया था। दिल्ली में इन आइटमों पर प्रतिबंध के बावजूद रोक

लेखक- सुशील देव

## आँखे खोलो इंडिया

### मताधिकार का सही उपयोग करें

अभी आम चुनाव का प्रथम चरण ही पूरा हुआ है पर ऐसा नहीं लगता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव जैसी कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही है। चारों ओर एक अजीब-सा सन्नाटा पसरा हुआ है। न तो गांव, और न ही कस्बों और शहरों में राजनैतिक दलों के होर्डिस और पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, और न ही लाऊडस्पीकर पर वोट मांगने वालों का शोर सुनाई दे रहा है, चाय के ढाबों और पान की दुकानों पर अक्सर जमा होने वाली भीड़ भी खामोश है। जबकि पहले चुनावों में ये शहर के वो स्थान होते थे जहां से मतदाताओं की नब्ज पकड़ना आसान होता था। आज मतदाता खामोश है। इसका क्या कारण हो सकता है। संभव है कि मतदाता तय कर चुके हैं कि उन्हें किस वोट देना है पर अपने मन की बात को जुबान पर नहीं लाना चाहते। क्योंकि उन्हें इसके संभावित दुष्परिणामों का खतरा नजर आता है। यह हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। जनसंवाद के कई लाभ होते हैं। एक तो जनता की बात नेता तक पहुंचती है और दूसरा ऐसे संवादों से जनता जागरूक भी होती है। अलबत्ता, शासन में जो दल बैठा होता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसकी नीतियों पर खुली चर्चा हो। दरअसल, उसे इससे माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। हर शासक यही चाहता है कि उसकी उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर मतदाता के सामने पेश किया जाए। इंदिरा गांधी से नरेन्द्र मोदी तक कोई भी इस मानसिकता का अपवाद नहीं रहा है। आम तौर पर यह माना जाता था कि मीडिया सचेतक की भूमिका निभाएगा। पर मीडिया को भी खरीदने और नियंत्रित करने पर हर राजनैतिक दल अपनी हँसियात से ज्यादा खर्च करता है जिससे उसका प्रचार होता रहे।



प्रकारिता में इस मानसिकता के जो अपवाद होते हैं वे यथासंभव निष्पक्ष रहने का प्रयास करते हैं ताकि परिस्थितियों और समस्याओं का सही मूल्यांकन हो सके। पर इनकी पहुंच बहुत सीमित होती है, जैसा आज हो रहा है। ऐसे में मतदाता तक सही सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। अधूरी जानकारी से जो निर्णय लिए जाते हैं, वो मतदाता, समाज और देश के हित में नहीं होते जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। सब मानते हैं कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत आमजन को अपनी इच्छा से चुनाव में खड़े हुए किसी भी प्रत्याशी को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। इस तरह चुने गए

प्रतिनिधियों से विधायिका बनती है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। आज भारत में जो परिस्थिति है, उसमें जनता प्रभित है। उसे अपनी सुनिश्चिता समस्याओं की चिंता है पर उसके एक हिस्से के दिमाग में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने यह बैठा दिया है कि नरेन्द्र मोदी अब तक के सबसे श्रेष्ठ और ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वे तीसरी बार फिर जीतकर आएं, जबकि जमीनी हकीकत अभी अस्पष्ट है। क्षेत्रीय दलों के नेता काफी तेजी से अपने इलाके के मतदाताओं पर पकड़ बना रहे हैं। और उन सवालों को उठा रहे हैं, जिनसे देश का किसान, मजदूर और

नौजवान चिंतित है। इसलिए उनके प्रति आम जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, इसलिए इंडिया0 गठबंधन के नेताओं की रैलियों में भी भीड़ आ रही है। जबकि भाजपा की रैलियों का रंग फीका है। हालांकि चुनाव की हवा मतदान के 24 घंटे पहले भी पलट जाती है। इसलिए पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। 1970 के दशक में हुए जयप्रकाश आंदोलन के बाद से किसी भी राजनैतिक दल ने आम मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है जबकि अगर ऐसा किया होता तो इन दलों को चुनाव के पहले मतदाताओं को खैरात बांटने और उनके सामने लंबे-चौड़े झूठे वादे करने की नौबत नहीं आती। हर दल का अपना एक समर्पित काइड होता जबकि आज काइड के नाम पर पैसा देकर कार्यकर्ता जुटाए जाते हैं, या

वे लोग सक्रिय होते हैं, जिन्हें सत्ता मिलने के बाद सत्ता की दलाली करने के अवसरों की तलाश होती है। ऐसे किराये के कार्यकर्ताओं और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव ही दल बदल का मुख्य कारण है। इससे राजनेताओं की और उनके दलों की साथ तेजी से गिरी है। एक दृष्टि से इसे लोकतंत्र के पतन का प्रमाण माना जा सकता है। हालांकि दूसरी ओर, यह मानने वालों की भी कमी नहीं है कि इन सब आंधियों को झेलने के बावजूद भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उसके करोड़ों आम मतदाताओं ने बार-बार राजनैतिक परिवर्तन का परिचय दिया है, जब उन्होंने बिना शोर मचाए अपने मत के जोर पर कई बार सत्ता परिवर्तन किए हैं। मतदाता की राजनैतिक परिपक्वता का एक और प्रमाण यह भी है कि अब निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। 1951 के आम चुनावों में 6 लक्ष निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे जबकि 2019 के चुनाव में इनकी संख्या घटकर मात्र 0.11 लक्ष रह गई। स्पष्ट है कि मतदाता ऐसे उम्मीदवारों के हाथ मजबूत नहीं करना चाहता जो अल्पमत की सरकारों से मोटी रकम ऐठ कर समर्थन देते हैं। मतदाताओं की अपेक्षा और विश्वास संगठित दलों और नेताओं के प्रति है। ऐसे में वे अपने कर्तव्य का सही से पालन करें। आम जन के रूप में हमें निराश नहीं होना है। हमारी हस्तभंग कोशिश होनी चाहिए कि हमारे परिवार और समाज में राजनीति के प्रति समझ बढ़े और हर मतदाता अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करे। कोई नेता या दल मतदाता को भेड़-बकरी समझ कर हांकने की जुरत न करे।

लेखक- विनीत नारायण

## विविध समाचार

### स्ट्रेस यह क्या होता है, अब आप यह कहेंगे

**विविध समाचार-**  
रोजाना कुछ देर डांस करके सेहतमंद बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स इसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए फायदेमंद मानते हैं। उनका कहना है कि डांस से पूरी बाँड़ी एक्टिव होती है और तनाव दूर हो सकता है। रोजाना कुछ देर डांस करके सेहतमंद बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स इसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए फायदेमंद मानते हैं। उनका कहना है कि डांस से पूरी बाँड़ी एक्टिव होती है और तनाव दूर हो सकता है। डांस सेहत के लिए फायदेमंद



माना जाता है। डांस करने से पूरी बाँड़ी एक्टिव होती है और तनाव दूर होता है। इसका मकसद डांसर्स का उत्साह बढ़ाना और डांस

के अलग-अलग फॉर्म को बढ़ावा देना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर दिन 15-20 मिनट डांस करके ही कई फायदे पा सकते हैं,

इसलिए अपना मनपसंद गाना लगाकर कुछ देर थिरक सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं डांस करने से सेहत को क्या-क्या फायदे मिलते हैं... डांस करने से फैंट बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डांस करना फायदेमंद हो सकता है। जुंबा, बेली, क्लासिकल, हिप हॉप करके मोटापा-वजन कम कर सकते हैं। रोजाना डांस करने से बाँड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हड्डियों में ताकत आ जाती है। डांस करने से मेमोरी बेहतर होती है। कुछ स्टडी में पाया गया है कि डांस करने से डिमेंशिया के लक्षण

भी कम हो सकते हैं। डांस करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। शरीर में सही तरह ब्लड पहुंचता है और कई अंग सही तरह काम करते हैं। डांस करने से तनाव दूर हो सकता है। इससे डिप्रेशन जैसी समस्याएं झट से दूर हो जाती हैं। इसे डिप्रेशन भगाने की अच्छी थैरेपी माना जाता है। थोड़ी देर डांस करके हार्ट को हेल्दी बनाया जा सकता है। यह एक शानदार कार्डियो वर्कआउट माना जाता है। 00एक नहीं है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या, जानें तीनों मेंटल कंडीशंस में क्या है अंतर

### तीनों मेंटल स्थिती में क्या होता अंतर

#### विविध समाचार-

एंजायटी और डिप्रेशन दोनों मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं। दोनों ही खतरनाक मानी जाती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर हमेशा इनसे बचने और सावधान रहने के लिए कहते हैं। कई बार सामान्य उदासी और तनाव को लोग एंजायटी और डिप्रेशन मान लेते हैं, जो गलत है। क्या आप एंजायटी और डिप्रेशन में अंतर जानते हैं? अगर नहीं तो इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं दोनों के बीच का फर्क...

**एंजायटी क्या होता है**  
यह एक तरह का ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसे चिंता, डर या आशंका से जोड़कर डॉक्टर देखते हैं। छोटी सी भी बात पर एकदम से घबरा जाना और बेचौन हो जाना इसके



लक्षण होते हैं। इसके अलावा किसी चीज से डरना और उसे सोच-सोचकर तनाव महसूस करना, दिल की धड़कनों का बढ़ना, ओवरथिंकिंग एंजायटी होता है। ऐसी स्थितियों होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलकर बात करनी

चाहिए।  
**एंजायटी के लक्षण**  
\* समय-समय पर बेचैनी  
\* चिड़चिड़ापन  
\* मांसपेशियों में तनाव  
\* ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई  
\* दिल की धड़कने बढ़ना

\* अधिक पसीना आना  
\* कांपना और सांस लेने में दिक्कतें  
**डिप्रेशन क्या होता है**  
डिप्रेशन यानी अवसाद मूड से जुड़ा डिसऑर्डर है, जिसकी चपेट में आने पर इंसान हमेशा उदास रहता है, किसी काम में

**डिप्रेशन के लक्षण**  
\* लगातार उदास रहना  
\* थकान, भूख या वजन में बदलाव  
\* नींद में गड़बड़ी, अपराधा की भावना  
\* ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई  
\* सुसाइड का ख्याल मन में आना

## दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 74 वाँ स्थापना दिवस

## आभासी तौर पर जुड़ी यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

## गोरखपुर, संवाददाता-

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 74वाँ स्थापना दिवस समारोह सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल वरुचल जुड़कर अध्यक्षता की। इस दौरान कुलपति ने 112 मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में कुलपति प्रो पूनम टंडन तथा विशिष्ट पुरातन छात्रों द्वारा जल संचयन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक सहित कुल 112 स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। महामहिम की गरिमायें उपस्थिति में मेधावियों विद्यार्थियों को 48 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक तथा 64 स्मृति स्वर्ण पदक दिया गया। इसके साथ ही युवा महोत्सव, सांस्कृतिक, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं तथा एन.एस.एस./एन.सी.सी. की विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके बाद ललित कला एवं संगीत विभाग के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगीत तथा कुलगीत की प्रस्तुति की गई।

कुलपति ने किया संबोधित वरुचल उद्घोषण में कुलाधिपति ने कहा कि किसी भी सभ्यता, किसी भी देश, किसी भी नगर की तरह संस्थाओं के इतिहास में स्थापना दिवस का विशेष महत्व होता है। वह दिन उसकी जीवन यात्रा का



प्रस्थान बिंदु होता है और उसके मूल्यांकन का पहला मानक भी स्थापना दिवस के आयोजन से जहां परंपराओं का स्मरण होता है तो वहीं वर्तमान प्रगति के मूल्यांकन और भविष्य की योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करने का अवसर भी प्राप्त होता है। गोरखपुर की पावन धरा का अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। यह महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोरक्षनाथ, संत कबीर दास आदि अनेक महापुरुषों की पवित्र भूमि रही है। मैं ऐसी पावन धरती को नमन करती हूँ।

दीनदयाल उपाध्याय की हुई बात उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ है। पंडित जी अत्यंत उच्च कोटि के दार्शनिक एवं विचारक थे, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भारतीय संस्कृति की बुनियाद पर ही निर्धारित और

नियोजित होनी चाहिए। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने सात दशकों से अधिक की अपनी अनवरत यात्रा में समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी है। यह आप सभी की कार्य कुशलता का ही परिणाम है कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में 'ए प्लस प्लस' श्रेणी प्राप्त कर देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। अभी हाल ही में आपने वयू0एस0वर्ल्ड रैंकिंग में दक्षिण एशिया क्षेत्र में दो सौ अठ्ठावनवीं (258वीं) की रैंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर पुनः अपने आपको प्रमाणित किया है। यूनिवर्सिटी के शिक्षक साल दर साल अपने विद्यार्थियों के Intellectual, Academic और Physical Development को निखारते हैं तथा छात्रों का सामर्थ्य बढ़ाते हैं। छात्र अपने सामर्थ्य को पहचानें, इसमें भी शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। विश्वविद्यालय को मिला यूजीसी से

## 7 पेटेंट रजिस्टर कराए

खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को समान रूप से प्रोत्साहित करते हुए हमने उत्कृष्ट शोध की ओर भी कदम बढ़ाया है। बीते एक माह में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 7 पेटेंट रजिस्टर कराए हैं। 15 पेटेंट स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। हमारा लक्ष्य इस वर्ष 50 नये पेटेंट रजिस्टर कराने का है। विश्वविद्यालय आज दो महत्वपूर्ण सेवाओं की शुरुआत कर रहा है। हमारे विद्यार्थी अपने अंकुशों,

ग्रेड 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा: कुलपति अपने स्वागत उद्घोषण में कुलपति प्रो पूनम टंडन ने कहा कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित यह प्रथम विश्वविद्यालय आज अपने अमूर्त काल में प्रवेश कर रहा है। यह विश्वविद्यालय देश के उन शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल है जिसे नैक मूल्यांकन में 'ए डबल प्लस' श्रेणी अर्जित करने के साथ साथ दुनिया भर की अनेक रैंकिंग सूचियों में अपना स्थान बनाया है। विश्वविद्यालय को भारत सरकार की पीएम-रूपा योजना के अन्तर्गत शोध एवं नवाचार के लिये चयनित करते हुए 100 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को ग्रेड 1 यूनिवर्सिटी के रूप में चिन्हित किया है। विश्वविद्यालय ने अथक परिश्रम से सत्र नियमन, परीक्षा और परिणामों की घोषणा में उल्लेखनीय सफलता पायी है। देश

उपाधियों को प्राप्त करने के लिये परेशान न हों और इन्हें परीक्षा से लेकर उपाधि तक घर बैठे प्राप्त हो सके, इसके लिये एक पोर्टल-SERVE का लोकार्पण माननीय कुलाधिपति जी के करकर्मलों से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सैमिंग इनोवेशन कैम्पस कार्यक्रम स्वदेश का भी शुभारम्भ हो रहा है जिसमें विद्यार्थियों को स्किल डेवेलोपमेंट के क्षेत्र में अनेक पाठ्यक्रम एवं अवसर प्राप्त होंगे।

ही नहीं दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों के साथ एमओयू साइन किये हैं। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। हम इस वर्ष से 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिये हैं। विवि पाठ्यक्रमों को यूजीसी एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप डिजाइन करने वाले अग्रणी परिसरों में से एक हैं।

पुरातन छात्रों को मिला सम्मान स्थापना दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट पुरातन छात्रों में पद्म श्री प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, चंद्रप्रकाश अग्रवाल, अतुल सराफ, डॉ एलके पाण्डेय, श्रीमती निर्मला एस चंदा, पूर्व आईपीएस जितेन्द्र प्रताप सिंह एवं भारतीय रेल सेवा के डॉ. स्वामी प्रकाश पाण्डेय को सम्मानित किया गया।

## अब खुले में करिए बीयर का सेवन

गोरखपुर, संवाददाता- देसी शराब खरीदकर तत्काल गटकने के लिए दुकान में ही इंतजाम होता है। लेकिन अंग्रेजी शराब और बीयर के शौकीनों को या तो मॉडल शॉप की तलाश करनी पड़ती है। या फिर सड़क या कार में ही जाम छलकाना होता है। ऐसे में कई बार अच्छे घरों के लोग भी पुलिस की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में आबकारी विभाग ने बीयर के दुकानदारों को सहूलियत दे दी है। अब बीयर का लाइसेंस लेने वाले 5000 रुपये का शुल्क लेकर दुकान से सटे ही स्थान देकर बीयर पीने की छूट दे सकते हैं।

आबकारी विभाग के नये आदेश के बाद अब बीयर के लाइसेंस सिर्फ 5000 रुपये सालाना फीस जमा कर बिठा की पिलाने की



## इस शर्त पर पिलाने की मिलेगी छूट

आबकारी विभाग की जिले में बीयर की 113 दुकानें हैं। विभाग द्वारा सभी लाइसेंसों को इस नई सुविधा की जानकारी दी जा रही है। आबकारी विभाग ने फीस जमा करने के लिए एक एकाउंट नंबर भी जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक, बीयर की दुकान से 20 मीटर के दायरे में ही बिठाकर पिलाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जहां बैठकर बीयर पीने की सुविधा मिलेगी उसका

सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ऐसे में आबकारी विभाग का राजस्व तो बढ़ेगा ही, शौकीनों को भी दिक्कत नहीं होगी। शौकीन

एरिया 100 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं यहां पीने के अलावा कुछ खाने का इंतजाम नहीं किया जा सकेगा। वैसे विभाग की तरफ से देसी शराब की दुकानों पर बिठाकर पिलाने की सुविधा पहले से ही है। वहीं अंग्रेजी शराब और बीयर के लिए मॉडल शॉप भी खुले हैं। जहां खाने की वस्तुएं भी मिलती हैं। लेकिन जिले की 13 मॉडल शॉप की फीस काफी अधिक होती है।

दलील देते हैं कि गर्मी में ठंडी बीयर के शौकीन सार्वजनिक स्थान पर पीते हैं तो हमें पुलिस के डंडे का खौफ रहता है। घर लेकर

जाएं तो परिवार और पत्नी का खौफ रहता है। एक शौकीन की दलील है कि दुकान से ठंडी बीयर चंद मिनटों में हलक के नीचे नहीं उतारा जाए तो वह गर्म हो जाती है। दुकान पर खड़े होकर पी नहीं सकते हैं। जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि विभाग की तरफ से बिठाकर बीयर पिलाने की सुविधा दी जा रही है। इसे लेकर सभी लाइसेंसों को सूचना दे दी गई है। जल्द ही फीस जमा करने के लिए हेड दे दिया जाएगा। जिसके बाद सभी लाइसेंसों को इसका लाभ मिलेगा।

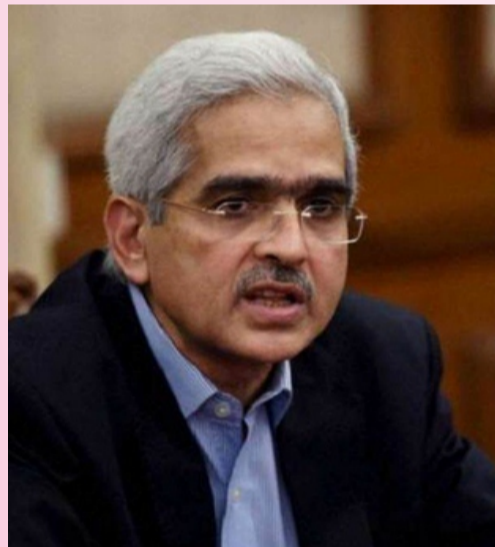
## नई मौद्रिक नीति पर गोरखपुरवासियों की राय लेने आ रही है आरबीआई की टीम

## गोरखपुर,

## आरएनएस-

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा तैयार की जा रही मौद्रिक नीति में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के लोगों का भी फीडबैक लिया जाएगा। आरबीआई की टीम 2 मई से गोरखपुर जिले के शहरी के साथ ही कस्बाई इलाकों में पहुंचकर लोगों की आर्थिक स्थिति का आंकलन करेगी। इसके लिए आरबीआई ने जिला प्रशासन और पुलिस से सहयोग मांगा है। आरबीआई की रिसर्च टीम द्वारा देश भर से जुटाए गए आंकड़ों के बाद ही मौद्रिक नीति में ब्याज दरों का निर्धारण होगा।

आरबीआई ने सर्वे को लेकर प्रदेश में गोरखपुर के साथ ही लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज को भी शामिल किया है। गोरखपुर में चार जगहों पर सर्वे होगा, जिसमें शहर और देहात का इलाका शामिल किया गया है। आरबीआई की टीम तय इलाकों में जाकर आम लोगों से मिलकर उनके औसतन



## 2 से 11 मई तक टीम करेगी सर्वे

आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की ओर सर्वे के लिए मुंबई की फर्म मेसर्स हेस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मा सौंपा गया है। इसकी टीम को दो से 11 मई के बीच में गोरखपुर आना है। आरबीआई की ओर से डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की गई है। पत्र में बताया गया है कि मौद्रिक नीति समिति

आदमनी और खर्च का डाटा तैयार करेगी, जिसमें सुझाव के आधार पर ब्याज दर को घटाने

को जानकारी देने के लिए द्विमासिक अंतराल पर देशभर में घरेलू सर्वेक्षण का काम हो रहा है। रिसर्च संस्था के कर्मचारी चयनित गांव, मोहल्ले में घरों में जाकर सर्वे को पूरा करेंगे। गोरखपुर के गोला तहसील के बड़हलगंज, सहजनवा तहसील के घुरियापार खास, गोला के ही गौर खास और शहर के पथरा इलाके में टीम जाएगी।

और बढ़ाने पर सरकार के अंतिम मुहर के बाद फैसला लिया जाता है। सीए अखिलेश्वर दूबे का

कहना है कि मौद्रिक नीति का तात्पर्य आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से ब्याज दरों, धन की आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग से है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी के साथ निहित है। यह जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य है।

## अब सूचना के अधिकार के उपयोग के लिए

## ऑनलाइन निकाले 10 रूपयें का ई-पोस्टल ऑर्डर

गोरखपुर, संवाददाता- पिछले डेढ़ दो साल से सूचना के अधिकार के तहत 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की जबरदस्त किल्लत है। सरकार पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वह सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली सूचना में आनाकानी को लेकर पोस्टल ऑर्डर का कृतिम किल्लत बनाए रखना चाहती है। लेकिन डॉक विभाग ने ई-पोस्टल ऑर्डर की सुविधा दी है। डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सिर्फ एक क्लिक में अपलोड किया जा सकता है।

नौकरियों में पोस्टल ऑर्डर की मांग घटने से सिर्फ आरटीआई के लिए ही 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की मांग रह गई है। गोरखपुर-बस्ती मंडल के सभी प्रधान डाकघर में कुछ माह पहले 10, 20 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की कमी हो गई थी। जो अभी भी बरकरार है। मजबूरी में लोगों को 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर खरीदने पड़ रहे थे। यह सब ई-आईपीओ का प्रचार-प्रसार न होने से हुआ। डाकघर के काउंटर पर



## ई-पोस्टल ऑर्डर

उपभोक्ता डाक विभाग की वेबसाइट [www.indiapost.gov.in](http://www.indiapost.gov.in) पर जाएं। ई-आईपीओ विकल्प को चुनें। रजिस्ट्रेशन के बाद पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं। जिसके नाम से पोस्टल ऑर्डर बनाना होता है, रजिस्ट्रेशन उसी के नाम से होना चाहिए। पोस्टल ऑर्डर की डिटेल्स भरें। ड्रॉप डाउन ऑप्शन में मिनिस्ट्री सर्व करें। वयूआर कोड के जरिए यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं।

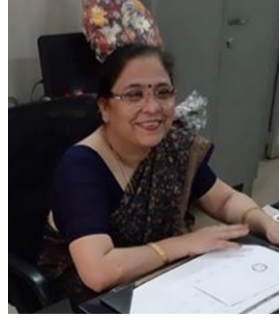
बैंठे कर्मचारी ने भी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ई-आईपीओ से खरीदने की जानकारी किसी को नहीं दी। बता दें कि गोरखपुर जिले में आरटीआई के लिए लोग प्रति माह 3 से 4 लाख रुपये कीमत के पोस्टल ऑर्डर खरीदते हैं। सूचना के अधिकार को हाथियार बनाने वाले आनंद रंगटा का कहना है कि इस सुविधा का प्रचार

प्रसार नहीं होने से हमें भटकना पड़ता था। अब इससे काफी सहूलियत होगी। प्रवर डाक अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि ई-आईपीओ विशेषकर आरटीआई के लिए बनाया गया है। ताकि सूचना मांगने वालों को दिक्कत न हो। यह अच्छी सुविधा है। घर बैठे इसका लाभ सभी उठा सकते हैं।

## गो0वि0वि0 की कुलपति ने लगाई शिक्षकों की क्लास

## गोरखपुर, संवाददाता-

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की झूठी करने कई शिक्षक नहीं पहुंचे। मंगलवार को कुलपति ने इन शिक्षकों को कार्यालय में चाय पर बुलाकर जमकर क्लास ली। उन्होंने सभी शिक्षकों से परीक्षा झूठी में अनुपस्थित रहने का कारण पूछा। सोमवार को परीक्षा झूठी में अनुपस्थित रहने वाले सभी शिक्षकों को मंगलवार को कुलपति कार्यालय से फोन करके शाम पांच बजे चाय पर बुलाया गया था। उन्हें इसका कारण नहीं बताया गया। कई शिक्षक इसको लेकर काफी उत्साहित थे। लेकिन जब कुलपति प्रो. पूनम टंडन



ने एक-एक कर परीक्षा झूठी में अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो उनके होश उड़ गए। कुछ शिक्षकों ने अलग-अलग कारण बताए। कुलपति ने कहा कि यदि किसी भी कारण से परीक्षा झूठी में नहीं पहुंच पाते तो इसकी सूचना केंद्राध्यक्ष को पहले दें और अपना विकल्प भी सुनिश्चित करें।

## दूल्हे से शादी कर प्रेमी संग लड़की फरार

## गोरखपुर, संवाददाता-

यूपी के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है। जहां शादी के पांच दिन बाद ही एक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। जब यह बात उसके दूल्हे को पता चली तो वह दंग रह गया। जानकारी के मुताबिक अभी युवती की विदाई नहीं हुई थी। उधर, लड़की के घर वालों ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है।

थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ तय हुई थी। 21 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में धूमधाम के साथ दोनों की शादी हुई। लड़की के पिता ने बताया कि उनके यहां शादी के 10 दिन बाद दुल्हन की विदाई करने का रिवाज है। सोमवार यानी 30 अप्रैल को विदाई होनी थी। इसे लेकर घर पर सारे कार्यक्रम चल रहे थे। जब परिजन युवती को लेने कमरे में पहुंचे तो वह गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद जब पता नहीं चला तो परिजन थाने पहुंचे और गांव के ही एक युवक पर भगाने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गांव के ही विनय यादव नाम का युवक बेटी को काफी समय से परेशान करता था।

## पुलिस से तेज निकले आरोपी

## गोरखपुर, आरएनएस-

व्यापारी से 50 लाख रुपये छीनने के मामले में फरार आरोपी चल रहे तीनों आरोपियों को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। न्यायाधीश सिद्धार्थ और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने तीनों की गिरफ्तारी पर त्वरित रोक लगा दी है। सरकारी अधिवक्ता को सात मई तक का समय दिया है। कहा है कि केस की फ्रेश फाइल लेकर कोर्ट में रखें। गोरखपुर कोर्ट में आरोपियों के अधिवक्ता राहुल तिवारी ने शनिवार को कोतवाली के पैरोकार के साथ कोर्ट में अरेस्ट स्टे दाखिल कर दिया। आरोपी दरोगा चौकी इंवारज के अलावा पुलिस ने तीन अज्ञात पर भी केस दर्ज किया था। जांच के दौरान



पुलिस ने तीन नामों को बढ़ाते हुए प्रचंड प्रताप सिंह, विशाल तिवारी और मुकेश को आरोपी बनाया। इनके खिलाफ एनबीडलूभी जारी किया गया था। क्राइम ब्रांच, एसओजी और

को सुनने के बाद सरकारी वकील से भी पक्ष मांगा गया, लेकिन वे नहीं दे सके। वहीं, आयकर विभाग ने व्यापारी नवीन श्रीवास्तव के घर समन चम्पा कर बयान के लिए संपर्क किया पर बयान दर्ज नहीं हो सका। पुलिस और आयकर विभाग इसे हवाला की रकम ही मान रही है। आयकर विभाग के पास जबतक नवीन श्रीवास्तव का लिखित बयान नहीं होगा, तब तक जब्त की गई रकम को आयकर विभाग अपने कब्जे में नहीं ले पाएगा। पकड़ा गया 44 लाख रुपये कोतवाली के मालखाने में पड़ा है। इधर, आयकर विभाग की तरफ से कोतवाली पुलिस को भी नवीन श्रीवास्तव को हाजिर करवाने का एक समन भेजा गया।

